The Hindu- 05- November-2022

A.P. and Telangana to survey Polavaram backwater effect

The Hindu Bureau
HYDERABAD

The Polavaram Project Authority (PPA) is taking up a joint survey on the backwater effect of the project in Telangana from November 8 with the help of engineers of the Irrigation/Water Resource Departments of Telangana and Andhra Pradesh.

A survey conducted by an expert committee set up by the Irrigation Department of Telangana recently has found that storage of water at full reservoir level of 150 feet/45.72 metres in the project would result in submergence of an additional 892 acres in six villages of four mandals for eight months a year and suggested that the PPA take up the land acquisition process with project cost.

A survey that was conducted earlier by the National Green Tribunal has found that the Polavaram backwater effect would be up to 18 km upstream in Kinnerasani river and up to 6 km upstream in Murreduvagu. The survey to be taken up from November 8 is intended to identify the impact areas of Polavaram backwater based on the NGT survey and also on the suggestion made by the Ministry of Jal Shakti.

The Pioneer- 05- November-2022

THE HOOGHLY BANKS & CHANGING TIMES

The river has played a big role in evolution of modern urban sites

RAINA **GHOSH**

River Hooghly is an archive of imperial histories, enmeshed in regional stories of labour, livelihood and politics. A muddy, aqueous terrain upstream of the Bengal Delta, the Hooghly, was the main channel through which the Ganga flowed into the Bay of Bengal until the 17th century, after which the course shifted significantly eastward.

It is also known as Bhagirathi-Hooghly, a name that is an apt reflection of this microcosm of myth and science. The first part acknowledges the myth of King Bhagirath's efforts to bring the Ganga from heaven. The other half is a reference to the reeds called hogla that grow widely along this tidal basin.

The river forms the easternmost and primary distributary of the mighty Ganga. It once nourished the medieval ports of Tamralipta (present-day Tamluk) and Satgaon (or Saptagram), and the later colonial settlements of Bandel, Chandannagar, Serampore, Rishra and, last but not the least, Calcutta. Although most of its 260 km (starting from Giria near Murshidabad) spans rural Rarh Bengal, the river has played a significant role in the evolution of modern 'urban' sites. It has contributed to the growth of one of the first metropolitan cities in the country — present-day Kolkata.

My fieldwork focuses on the 'ghat spaces' along the Hooghly. To study how ghats signify unique river-city relationships, I pursue a framework of 'hydrosocial relations' based on the work of Jamie Linton and Jessica Budds in 2014. The two scholars proposed the hydrosocial cycle framework that explores the entangled nature of water-society relations.

To capture the different forms of everyday engagement on the edge of the water, I walked along the ghats between Barrackpore (north of Kolkata) and Budge Budge (south of Kolkata). I documented the daily practices of people both during busy and quieter times. There are three aspects unique to this edge -- the extractive economy around brick production using the river's silt (in the Batanagar-Budge Budge stretch); commerce around the ghats, including sales of ritualistic commodities (at Sovabazar and Nimtala Ghat), and flowers at Asia's largest wholesale flower market (at Mullick Ghat, Howrah), and different forms of leisure across the different ghats from north to south.

The communities thus include brick kiln workers, flower sellers, priests, men running the ferry service and loaders at the wholesale market – mostly a constituency of working-class men and women from lower castes and also non-native communities.

In the course of my field exercise, two things became evident to me: one was the distinct nature of the active urban edge of the river comprising 'city-makers'. The city-makers, through their labour, help in the everyday running of the city. Secondly, there was a clear tussle between whether to project ghats as fronts to the city or as its decaying backyard.

There has been a steady decline in the importance of the ghats with the growth of the city and the proliferation of transport systems beyond the historical Hooghly waterway. Government programmes to revive the ghats involve capital-intensive measures that threaten to erase the existing interactions between the river, the city and the livelihood of people entangled in it.

Unfortunately, this accompanies the silent erasure of the everydayness that persists today. Through this field exercise, I was convinced of the need to rethink the river's edges as non-binary fringes between land and water, which acknowledge the ephemerality of flows and fluxes of people and their daily activities. We need to understand the nuanced realities of ghats as essentially workspaces lying at the intersections of caste, class and gender. So, unless we look beyond rivers, to the multiple spaces and scales that they nurture, our plans would be limited, faulty and only disrupting landscapes.

देशभर के एक हजार से अधिक क्षेत्रों में भूजल दोहन चिंताजनक

ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। इंडिया वाटर वीक-2022 में दोहन से खराब होती भूजल की स्थिति से लोगों को आगाह किया जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भूगर्भ जल संचयन के लिए नई तकनीक बताने और आमजन को जागरूक कर रहा है। रिपोर्ट बताती है कि देशभर में 1114 क्षेत्रों में अत्यधिक भूजल दोहन होता है, जबकि 270 क्षेत्र ऐसे हैं, जहां भूजल दोहन गंभीर श्रेणी में है।

हालत यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में भूजल स्तर 20 से 45 मीटर तक पहुंच गया। ऐसे हालात में जल दोहन की मौजूदा स्थिति से निपटना चुनौती बन गया है। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सातवें इंडिया वाटर वीक-2022 का आयोजन चल रहा है। इसमें आयोजित हो रहे सत्रों में भूगर्भ जल के दोहन पर चिंतन हो रहा है। पानी को बचाने पर बात हो रही है। उसके संतुलित उपयोग पर भी विशेषज्ञ जोर दे रहे हैं।

सेंट्रल ग्राउंड वाटर जल बोर्ड भी भूजल की खराब होती स्थिति से आमजन को रूबरू करा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि देश में भूगर्भ जल का दोहन लगातार बढ़ रहा है। यह चिंतानजक है।

ग्रेनो के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित भारत जल सप्ताह के चौथे दिन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल पहुंचे। • हिन्दुस्तान

97 क्षेत्र में खारा पानी

रिपोर्ट बताती है कि 4427 क्षेत्र (करीब 64 प्रतिशत) भूजल दोहन के मामले में सामान्य स्थिति में मिले हैं। यह क्षेत्र 15.67 लाख वर्ग किमी का है। 97 क्षेत्र (एक फीसदी) क्षेत्र में पानी खारा है। इसके चलते यह पानी पीने योग्य नहीं है।

दिल्ली में भी हालात खराब

सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड दिल्ली के प्रभारी डॉ. एसके मोहिद्दीन बताते हैं कि मई 2022 की रिपोर्ट काफी खराब है। दिल्ली में बहुत से क्षेत्रों में जल स्तर बेहद संवेदनशील स्तर पर पहुंच गया है। 24 प्रतिशत में भूजल स्तर 20 से 45 मीटर तक है।

File No.T-74074/10/2019-WSE DTE

Punjab Kesari- 05- November-2022

सुखद व सुरक्षित माहौल के कारण निवेशकों की पहली पसंद बना हरियाणा

3आर के सिद्धांत पर जल प्रबन्धन की दिशा में कदम बढ़ रही है सरकार : मनोहर

जापानी कम्पनी ने लगाया हरियाणा में वाटर ट्रीटेड प्लांट, 4000 युवाओं को मिलेगा रोजगार

पलवल, भगत सिंह (पंजाब केसरी): हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार 3 आर- रिड्यूज, रिसाइकल और रियूज के सिद्धांत पर काम कर रही है। पानी के उचित प्रबन्धन के लिए ट्रीटेड वाटर पालिसी बनाते हुए जल संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार के इस महत्वाकांक्षी सिद्धान्त में विदेशी कंपनी निवेशक बनते हुए सहयोगी बन रही हैं । मुख्यमंत्री शुक्रवार को पलवल जिला के गांव देवली में जापान की कम्पनी डायकी एक्सिस के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कम्पनी के उद्घाटन उपरांत जल प्रबन्धन के लिए बनाए जा रहे उत्पादों की भी जानकारी ली। उद्घाटन अवसर पर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दूधोला व डायक्री एक्सिस कम्पनी के बीच विद्यार्थियों के कौशल निखार को लेकर एमओयू भी साइन किया गया।

मुख्यमंत्री ने एकादशी पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में सुखद व सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा रहा है और यही कारण है आज विदेशी निवेशकों की हरियाणा पहली पसंद बन रहा है। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ के निवेश के साथ देवली में स्थापित किया यह संयंत्र जल संरक्षण की दिशा में भागीदार बनने के साथ ही क्षेत्र के विकास में अहम रहेगा। उन्होंने बताया कि आने वाले 5 सालों में यह प्रतिष्ठित कम्पनी करीब 4000 लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराते हुए क़रीब 800 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हरियाणा टॉप रेंक में है और यही कारण है कि आज हरियाणा प्रदेश में 28 फीसदी जापान की कम्पनी निवेशक बन रही हैं। इस अवसर पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा,पृथला के विधायक नयनपाल रावत,पलवल के विधायक दीपक मंगला,होडल के विधायक जगदीश नायर,मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड़, पवन जिंदल,ओवरसीज निदेशक सीनिया टकोका,पर्यावरण मंत्रालय जापान की प्रतिनिधि नागई मिहोका, हिरोकी ऑग्मे,सीएम के मीडिया कॉर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ,श्री विश्वकर्मा कौशल वशिवविद्यालय के उप कुलपति डॉ राज नेहरू, डायक्री एक्सेस के डायरेक्टर रियो वाजा, सीईओ कमल तिवारी,पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल,एडीसी हितेष कुमार सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कम्पनी डायकी एक्सिस का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ।

जल संशोधन में डायकी एक्सिस का योगदान सराहनीय : गुर्जर

केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि डायक्री एक्सेस कंपनी द्वारा ऐसे इक्विपमेंट बनाये जाएंगे जो बेकार पानी का शोधन करके उसे उपयोग करने के लायक बनायंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच आपसी समझौता हुआ है,जिसके परिणाम स्वरूप यह उद्योग फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में लगा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में पानी को रिसाइकिल करके उसे उपयोग योग्य बनाने का काम चल रहा है। भारत में भी खराब पानी को उपयोग लायक बनाने में डायकी एक्सेस प्रबंधन का अहम योगदान रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत करते हुए डायक्री एक्सिस ग्रुप जापान के चेयरमैन हिरोशी ओगमे ने कहा कि कंपनी ने 60 वर्ष पूर्व भारत में उधोग लगाने की शुरुआत की थी। भारत और जापान के बीच निवेश को लेकर अच्छे रिश्ते हैं। उन्हें उम्मीद है कि आगे भी उन्हें सरकार का सहयोग मिलता रहेगा।

जल प्रबंधन का बेहतर प्रोजैक्ट पलवल में : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल प्रबंधन की दिशा में सरकार के साथ ही यह कंपनी बेहतर प्रोजेक्ट लेकर पलवल में आई है। उन्होंने कहा कि यह कम्पनी ट्रिटेड वॉटर के लिए कार्य करेगी। पानी को आज के समय में बचाना बहुत जरूरी है, गंदे पानी को ट्रीटमेंट कर के दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। नई नई तकनीक के माध्यम से हम वॉटर ट्रीटमेंट कर के इस्तेमाल करने के कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश में अब तक 200 एसटीपी लगे हैं और उनसे लगभग 700 क्यूसिक पानी को रियूज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 2030 तक पानी का सदुपयोग करते हुए 80 फीसदी रीयूज करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें हरियाणा अपना सक्रिय योगदान देगा। उन्होंने कहा कि जितना पानी हम दिल्ली को दे रहे हैं उसका 67 प्रतिशत से ज्यादा खराब पानी हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इस कंपनी के माध्यम से भी कई प्रोजेक्ट बनाकर पानी साफ कर इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योग क्षेत्र में सरकार ने ट्रीटेड वॉटर को लेकर पॉलिसी बनाई है ताकि पहले ट्रीटेड वॉटर का इस्तेमाल हो सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पानी की गुणवत्ता पर पूरा फोकस सरकार का है और जल प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार सामाजिक सहभागिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि माइक्रो इरिगेशन के तहत खेती करने वाल्य किसानों को सरकार की ओर से 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।

Amar Ujala- 05- November-2022

यमुना में नहीं बहेगा दूषित पानी अपग्रेड होगा कोंडली एसटीपी

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया एसटीपी व गाद उपचार संयंत्र का निरीक्षण

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार 2025 तक यमुना की सफाई के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। शुक्रवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोंडली स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और 'गाद उपचार संयंत्र' का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को 45 एमडीजी क्षमता वाले एसटीपी को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड कर सीवेज के पानी को बेहतर तरीके से शोधित करने के निर्देश दिए। उन्होंने तय समय में इस काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही देरी होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

इस दौरान सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के विभिन्न इलाकों में विभिन्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने व यमुना की सफाई को लेकर चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। सरकार ने यमुना नदी को 2025 साल में पूरा साफ करने का लक्ष्य रखा है। यमुना तक साफ पानी पहुंचे इसी कड़ी में कोंडली में 45

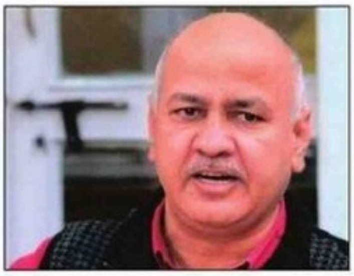

एमडीजी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड किया जाएगा।

अधिकारियों को फटकार : उपमुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान लापरवाही को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही एक सप्ताह में प्लान ऑफ़ एक्शन देने का निर्देश दिया है। साथ ही कंपनी पर जुर्माना लगाने का भी निर्देश दिया है। कोंडली में मौजूदा 45 एमडीजी क्षमता वाले एसटीपी में बीओडी/टीएसएस को 20/30 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से सीवर के पानी को उपचारित करने के लिए डिजाइन किया गया था।

रोजाना 200 टन गाद किया जा रहा उपचारित : उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र की रोजाना 200 टन गाद (कीचड़) उपचार करने की क्षमता है। गाद उपचार संयंत्र गर्म हवा के ऑक्सीडाइजेशन की तकनीक पर आधारित है, जिसमें गर्म हवा का उपयोग करके गाद को सुखाया जाता है और बायोचार में परिवर्तित किया जाता है।

वादों के बाद भी नदी की सफाई नहीं : बिधूड़ी

नई दिल्ली। यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के दावे पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि वादों के बाद भी दिल्ली सरकार यमुना को साफ नहीं कर पाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2013, 2015 और 2020 चुनाव में दावा किया था कि यमुना को साफ कर उसमें डुबकी लगवाऊंगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर प्रतिदिन 768 मीलियन गैलन सीवेज उत्पन्न होता है लेकिन उनमें से सिर्फ 34 मीलियन गैलन सीवेज का ही ट्रीटमेंट किया जाता है बाकी पिछले आठ साल बितने के बाद भी सीधे यमुना में गिरते हैं। ब्यूरो